उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 अंक 12 16-30 जून 2022 ₹ 20/-

पैगम्बर की तौहीन के बहाने निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्याएं

- बिहार में ओवैसी को जोरदार झटका
- अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही
- इजरायली संसद भंग और नया चुनाव
- ब्रिटेन में हजरत फातिमा पर बनी फिल्म पर पाबंदी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पैगम्बर की तौहीन के बहाने निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्याएं 04
मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी 08
बिहार में ओवैसी को जोरदार झटका 10
महाराष्ट्र में नगरों के नामों में परिवर्तन 11
राष्ट्रपति का चुनाव उर्दू समाचारपत्रों की नजर में 12

विश्व

अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही 14
पाकिस्तान को आर्थिक दिवालियापन से बचाने का प्रयास 15
काबुल में गुरुद्वारे में धमाका 17
अमेरिका में गन कल्चर को रोकने के प्रयासों को झटका 18
बलूचिस्तान में मजदूरों के शिविर पर विद्रोहियों का हमला 19

पश्चिम एशिया

इजरायली संसद भंग और नया चुनाव 20
इरान और सऊदी अरब के संबंध सुधारने हेतु इराक प्रयासरत 21
इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में जनरल गिरफ्तार 22
तुर्की और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास 23
ईरान में तीन महीने में सौ से अधिक लोगों को फांसी 25

अन्य

ब्रिटेन में हजरत फातिमा पर बनी फिल्म पर पाबंदी 26
संयुक्त राष्ट्र संघ में उर्दू और हिंदी 26
बेंगलुरु में इदगाह की भूमि पर विवाद 27
सऊदी अरब सरकार द्वारा इस्लामिक आतंकियों को मृत्युदंड का स्वागत 27
ब्रिटिश टीवी चैनल बीबीसी पर जुर्माना 27

सारांश

पैगम्बर-ए-इस्लाम की कथित तौहीन को लेकर विश्व भर में भारत सरकार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, उसके पीछे इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में यह बात भी उल्लेखनीय है कि जब ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में एक टेलीविजन चैनल पर बहस हो रही थी तो एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता तसलीम रहमानी ने भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उत्तेजित होकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद और उनकी पत्नी हजरत आयशा के बारे में कुछ शब्द कहे। खास बात यह है कि नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वह इस्लाम की अनेक मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हिस्सा है और विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक खुलेआम अनेक बार उसकी चर्चा कर चुका है। इसके बावजूद पैगम्बर की कथित तौहीन का मामला पहले भारत में कुछ स्वार्थी तत्वों ने उछाला और बाद में इसे मुस्लिम देशों ने लपक लिया। वातावरण को देखते हुए भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया और एक अन्य नेता नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, मगर इसके बावजूद यह तूफान थमा नहीं।

दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का 57 इस्लामिक देशों की सहयोग परिषद और खाड़ी परिषद में काफी प्रभाव है। पाकिस्तान के दबाव पर इन संगठनों ने भी भारत विरोधी प्रचार जोरों से शुरू कर दिया। भारत के अनेक नगरों में मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन किए और सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन उग्र प्रदर्शनों के पीछे कुख्यात मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट, आईएसआईएस और अलकायदा का हाथ है। इस जहरीले माहौल के कारण उदयपुर में दो मुस्लिम आतंकवादियों ने एक निर्दोष हिंदू व्यक्ति कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर दी और अपने इस कुकृत्य का वीडियो बनाकर उसे बाकायदा सोशल मीडिया में वायरल किया। कहा जाता है कि इन हत्यारों के संबंध सऊदी अरब और पाकिस्तान से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूरे मकड़जाल का पता लगाने का प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि उर्दू के अधिकांश अखबारों ने एक महीने तक नूपुर शर्मा के खिलाफ तो खूब जहरीला प्रचार अभियान चलाया, मगर किसी भी उर्दू अखबार ने पुलिस के उस बयान को प्रकाशित नहीं किया, जिसमें इन आरोपियों का संबंध पाकिस्तान और सऊदी अरब से बताया गया था।

ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के अमरावती में भी हुई है। यहां पर कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने उमेश कोल्हे नामक एक केमिस्ट को मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने तो पहले इसे लूटपाट की घटना बताकर मामले पर लीपापोती करने का प्रयास किया था, मगर जनता के दबाव पर बाद में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया, जिसने इस हत्या के संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

इजरायल में नाफ्ताली बेनेट की सरकार गिर गई है। इस सरकार के गठबंधन में आठ ऐसे दल शामिल थे जो वैचारिक दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी थे। इनकी आपसी खींचतान के कारण चार सांसदों ने संसद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण नाफ्ताली बेनेट सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अब इस वर्ष के अंत तक इजरायल में नए चुनाव होने की संभावना है। इजरायल की राजनीतिक अस्थिरता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि गत चार वर्षों में पांचवी बार संसद के चुनाव होने वाले हैं।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आर्थिक नीतियों को दोषी ठहराया है। अब पाकिस्तान सरकार चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि अनेक देशों से आर्थिक सहायता की भीख मांग रही है।

राष्ट्रीय

पैगम्बर की तौहीन के बहाने निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्याएं

विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा इस्लाम के पैगम्बर की तौहीन के आरोप लगाकर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ जो जहरीला वातावरण पिछले एक महीने से तैयार किया जा रहा था, उसके कारण दो मुस्लिम आतंकवादियों ने उदयपुर के एक निर्दोष दर्जी कन्हैयालाल को दिनदहाड़े निर्मम हत्या कर दी। खास बात यह है कि हत्यारों ने अपने इस कुकृत्य का बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक को कत्ल करने की धमकी दी गई। समाचारपत्रों के अनुसार इस खौफनाक हत्याकांड की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राजस्थान पुलिस की विशेष जांच टीम ने संभाल लिया है। दोनों हत्यारों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ के बाद उनके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। अभी इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है।

रोजनामा सहारा (4 जुलाइ) के अनुसार महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या भी तौहीन-ए-रसूल के सिलसिले में की गई है। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी थी, जिसने इस हत्या के मास्टरमाइंड इरफान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या के सिलसिले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अखबार-ए-मशरिक (30 जून) के अनुसार पूरे राजस्थान में इंटरनट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी डिविजनल कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर चिंता प्रकट की है और मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपये का चेक पेश किया है और दो व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इस घिनौनी घटना से सदमे में हूं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हालांकि इस घटना की निंदा की है और इसे इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बताया है, मगर उन्होंने पुलिस पर यह

आरोप लगाया है कि उसने आज तक गुस्ताख-ए-रसूल नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया है।

औरंगाबाद टाइम्स (30 जून) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामा मस्जिद के शाही इमाम और ओवैसी ने इस घटना की निंदा की है और मुसलमानों से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा है कि इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है। रियाज अटारी और गौस मोहम्मद नामक दो व्यक्तियों ने कन्हैयालाल नामक एक व्यक्ति को रसूल के नाम पर जिस तरह से मारा है, वह इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है।

कौमी तंजीम (9 जून) के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अलकायदा मुसलमानों का रक्षक नहीं बल्कि एक मुसीबत है, जो इस्लाम का लिबास ओढ़कर इंसानियत को लहूलुहान कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की आजादी इस देश में मुसलमानों को प्राप्त है उसकी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 जून) के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने कन्हैया के दोनों हत्यारों का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया है। राजस्थान के गृह राज्यमंत्री राजेंद्र यादव के अनुसार मोहम्मद गौस पाकिस्तान, सऊदी अरब और नेपाल में रहकर आया था। उसके तार कराची के एक संगठन दावत-ए-इस्लामी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश भर में दावत-ए-इस्लामी के जाल का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

अवधनामा (30 जून) के अनुसार राजस्थान में अनेक स्थानों पर भीड़ ने पथराव किया है। उदयपुर के वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से इंकार कर दिया है।

अवधनामा (30 जून) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह सोची-समझी हत्या है, जिसके लिए हत्यारों ने पहले ही योजना बनाई थी। उन्होंने यह धमकी दी थी कि कन्हैयालाल को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने नूपुर के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। कन्हैयालाल ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि उसकी जान खतरे में है। कई दिन तक उसने अपनी दुकान तक बंद रखी थी। बताया जाता है कि उदयपुर पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय कन्हैयालाल पर दबाव डालकर उसस समझौता करवा दिया। भाजपा ने यह मांग की है कि आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाए।

उर्दू के सभी समाचारपत्रों ने टीवी डिबेट में भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को खूब उछाला और उसे पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन की संज्ञा दी।

सहाफत (31 मई) के अनुसार एक टीवी शा में ज्ञानवापी पर बहस चल रही थी। इसी दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति तसलीम रहमानी ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिससे उत्तेजित होकर नूपुर शर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जो पैगम्बर-ए-इस्लाम और उनकी पत्नी से संबंधित थे। जब 'ऑल्ट न्यूज' वेब पोर्टल के मोहम्मद जुबैर ने यह वीडियो क्लिप अपनी

वेबसाइट पर डालो और उसे ट्विटर पर साझा किया तो इसके बाद देश और विदेश में बवाल मच गया। तीन दर्जन से ज्यादा स्थानों पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने घोषणा की कि कोई मुसलमान टीवी पर होने वाली बहसों में हिस्सा न ले।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस (8 जून) के अनुसार अलकायदा के भारतीय चैप्टर ए.क्यू.आई.एस. ने चेतावनी दी है कि पैगम्बर मोहम्मद की तोहीन के खिलाफ दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में आत्मघाती हमले किए जाएंगे। इस संदेश में कहा गया है कि अलकायदा भगवा आतंकियों को दिल्ली मुंबई उत्तर प्रदेश और गुजरात में खत्म करके ही दम लेगी। न वे अपनी घरों में सुरक्षित होंगे और न हो सैनिक छावनियां ही उन्हें बचा पाएगी। अलकायदा ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर के मुसलमान खून के आंसू रो रहे हैं और हम बदला लेकर रहेंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी के बाद सतर्क हो गई हैं। इस परिपत्र में गजवा-ए-हिंद (भारत में इस्लामिक जिहाद) का भी उल्लेख किया गया है और धमकी दी गई है कि हम भारत के शासकों के लिए तबाही और मौत का पैगाम लाएंगे।

अवधनामा (7 जून) के अनुसार तौहीन-ए-रसूल की विश्व भर में घोर निंदा हुई है। अरब देशों के सुपर मार्केट में भारतीय वस्तुओं के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भी इस घटना की निंदा की है। ओआईसी के बयान को भारत सरकार ने संकीर्ण सोच वाला और शरारतपूर्ण बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि ओआईसी की टिप्पणी गलतफहमी और शरारत पर आधारित है और भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है।

अवधनामा (6 जून) के अनुसार विदेशों में मचे भारी बवाल के बाद भाजपा ने इन आपत्तिजनक बयानों से अपने आप को अलग कर लिया है और कहा है कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसके साथ ही पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मालदीव की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इस घटना की निंदा की है।

इत्तेमाद (7 जून) के अनुसार दो दर्जन से अधिक मुस्लिम देशों ने तौहीन-ए-रसूल की घटना की निंदा की है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ईरान, कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस घटना की ओर उनका ध्यान दिलाया है। भारतीय राजदूतों ने कहा है कि भारत सरकार पैगम्बर-ए-इस्लाम की शान में किसी गुस्ताखी को कबूल नहीं करती और ये हरकत छोटे-मोटे लोगों की है, जिसे महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ओमान के मुफ्ती आजम ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जून) के अनुसार पैगम्बर-ए-इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ पूरा इस्लामिक जगत जबर्दस्त विरोध प्रकट कर रहा है। लीबिया ने भारत का बहिष्कार करने का फतवा जारी किया है।

हमारा समाज (7 जून) ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि अरब जगत के दबाव के कारण मोदी जैसे व्यक्ति को घुटने टेकने पड़े हैं। समाचार पत्र का कहना है कि पहली बार आया है 'ऊंट पहाड़ के नीचे'।

इत्तेमाद (7 जून) के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने मांग की है कि भारत सरकार जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन करने से रोके। जबकि आतंकवादी इस्लामिक संगठन हमास का कहना है

कि तौहीन-ए-रिसालत के दोषियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

अखबार-ए-मशरिक (7 जून) ने अपने संपादकीय में इस्लामिक जगत में हुई जबर्दस्त प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि आलम-ए-इस्लाम में कोहराम मचा हुआ है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन ने भी पैगम्बर-ए-इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वह भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है।

अखबार-ए-मशरिक (8 जून) के अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि वह पहले अपने दामन में झांके कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या दुर्गति हो रही है। ऐसी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान सरकार जानबूझकर इस मामले को हवा दे रही ह।

अखबार-ए-मशरिक (9 जून) ने मुख्य समाचार के रूप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, ओमान, मालदीव और इंडोनेशिया ने तौहीन-ए-रसूल की घटना की निंदा की है।

सहाफत (4 जून) के अनुसार बरेलवी दरगाह के प्रमुख एवं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने नूपुर शर्मा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

हमारा समाज (12 जून) के अनुसार मौलाना तौकीर रजा ने इस घटना के खिलाफ एक जनसभा का भी आयोजन किया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 मई) के अनुसार गुस्ताख-ए-रसूल नुपूर शर्मा और टाइम्स नाऊ के खिलाफ महाराष्ट्र में नौ स्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि रसूल की शान के लिए प्रत्येक मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकता है।

हमारा समाज (30 मई) के अनुसार मुंबई की रजा एकेडमी ने नूपुर शर्मा और टाइम्स नाऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जून) के अनुसार मुंबई पुलिस ने नूपुर शर्मा को समन जारी करके पुलिस थाने में तलब किया है। एक अन्य समाचार के अनुसार काबा के प्रमुख शेख सुदैस सहित 200 से अधिक मुस्लिम इमामों ने इस घटना की निंदा की है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक विश्वविद्यालय जामिया अल-अजहर ने मुसलमानों से अपील की है कि वे भारत के खिलाफ विरोध प्रकट करें।

सियासत (18 जून) के अनुसार अमेरिका ने भी पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन पर भाजपा के प्रवक्ताओं की निंदा की है।

सियासत (10 जून) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अता हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां को भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आश्वासन दिया है कि सरकार शान-ए-रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को ऐसा सबक सिखाएगी जो एक मिसाल बनेगी। डोवाल ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करके उन्हें यह आश्वासन दिया कि मोदी सरकार पैगम्बर की शान में किसी भी गुस्ताखी को सहन नहीं करेगी आर इस तरह की गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि डोवाल के इस आश्वासन का ईरान ने समर्थन किया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 जून) के अनुसार गुस्ताख-ए-रसूल के खिलाफ देश भर में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। रांची में हुई फायरिंग में दो व्यक्ति मारे गए हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद और जामिया मिलिया इस्लामिया में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। इलाहाबाद में पत्थरबाजी हुई है और अनेक वाहन फूंक दिए गए हैं। सहारनपुर और देवबंद में लाठीचार्ज हुआ है और भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मधय प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सैकड़ों स्थानों पर मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन किए हैं और गुस्ताख-ए-रसूल की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जून) के अनुसार कानपुर में हुई हिंसा का प्रमुख आरोपी हयात जफर हाशमी का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिश्ता पाया गया है। कानपुर पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पॉपुलर फ्रंट ने पश्चिम बंगाल और मणिपुर में हड़ताल का ऐलान किया था। हैरानी की बात यह है कि उसी दिन भारत के अनेक भागों में हिंसा सुनियोजित ढंग से भड़काई गई।

मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जून) के अनुसार टाइम्स नाऊ की पत्रकार नाविका कुमार क शो पर पैगम्बर रसूल के बारे में गुस्ताख टिप्पणी का पर्दाफाश करने वाले 'ऑल्ट न्यूज' के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद जुबैर 'ऑल्ट न्यूज' के नाम से एक फैक्ट चकिंग वेबसाइट चलाते हैं। इस गिरफ्तारी की दिल्ली प्रेस क्लब और अन्य कई पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्विट किया है कि जुबैर को गिरफ्तार करना सच्चाई पर हमला है, इसलिए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। 'ऑल्ट न्यूज' के संस्थापक प्रतोक सिन्हा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर को एक अलग मुकदमे में पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर उन्हें तीन वर्ष पहले के एक ट्विट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि जुबैर के खिलाफ एक हिंदू संगठन की ओर से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैराबाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

अखबार-ए-मशरिक (30 जून) के अनुसार जुबैर को पुलिस ने पटियाला हाउस के एक अदालत में पेश किया था और उन्हें चार दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि जुबैर को जानबूझकर पुलिस ने एक फर्जी मुकदमे में फंसाया है। जिस मामले में उन पर ट्विट करने का आरोप है वह 1983 की एक फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है और सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया हुआ है।

सालार (30 जून) के अनुसार जुबैर की गिरफ्तारी की संयुक्त राष्ट्र संघ ने निंदा की है और कहा है कि पत्रकारों को उनके लेखन, ट्विट और बयान पर जेल में नहीं डालना चाहिए। दुनिया में कहीं भी यह जरूरी है कि लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता हो। सरकार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

हमारा समाज (29 जून) के अनुसार जुबैर की गिरफ्तारी पर राजनीति में जबर्दस्त उबाल आया हुआ है और इस मामले पर विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विट में लिखा है कि हर कोई जो भाजपा की नफरत और झूठ को बेनकाब करता है वह सरकार के लिए खतरा है। ए.आई.एम.आई.एम. के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जुबैर की गिरफ्तारी निंदनीय है। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और जो सरकार की गलत हरकतों का पर्दाफाश करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृहमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई सच्चाई पर हमला और एक विशेष संप्रदाय के साथ भेदभाव का व्यवहार का संकेत है। 'ऑल्ट न्यूज' का काम झूठी सूचना के फैलाव का पर्दाफाश करना और सच्चाई को पेश करना है। उन्होंने शिकायत की है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करने वाले खुले घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की पुलिस के पास फुर्सत नहीं है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि जुबर को एक अलग केस में गिरफ्तार

किया गया है जो कि 2018 में उन्होंने ट्विट किया था। इस ट्विट में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसका शीर्षक दिया, '2014 से पहले हनीमुन होटल, 2014 के बाद हनुमान होटल'। पुलिस का दावा है कि उनके इस ट्विट से एक संप्रदाय की भावना आहत हुई है।

इत्तेमाद (29 जून) के अनुसार जुबैर ने यह दावा किया है कि उन्हें मजहब और पेशे के कारण निशाना बनाया गया है, क्योंकि वे झूठ का पर्दाफाश करते हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जुबैर के वकील ने कहा कि आरोपी ने अपने ट्विट में जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया है वह ऋषिकेश मुखर्जी की 1983 की फिल्म 'किसी से न कहना' का है और इस फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मगर अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

बिहार में ओवैसी को जोरदार झटका

मुंबई उर्दू न्यूज (29 जून) के अनुसार बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (ए. आई.एम.आई.एम.) को जोरदार झटका लगा है। उसके चार विधायक राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल हो गए हैं। इससे पूर्व अचानक तेजस्वी यादव ने बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के कमरे में ए.आई. एम.आई.एम. के चार विधायकों के साथ मुलाकात की थी, उनमें बिहार मजलिस के अध्यक्ष अख्तरूल इमान शामिल नहीं थे। जो चार सदस्य आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें मोहम्मद इजहार असफी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजर नईमी शामिल हैं। अब आरजेडी बिहार विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके विधायकों की संख्या 80 पहुंच गई है। जबकि भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी होगी, जिसके विधायकों की संख्या 77 है। उत्तर प्रदेश में भो ओवैसी को तब गहरा झटका लगा था जब चुनाव के बाद मजलिस के नेता गुड्डू जमाली ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया था। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें गुड्डू जमाली ही एक ऐसे उम्मीदवार थे, जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी। शेष सभी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। गुड्डू जमाली बाद में बीएसपी में शामिल हुए। उन्होंने आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, मगर हार गए।

रोजनामा सहारा (30 जून) के अनुसार ए. आई.एम.आई.एम. सीमांचल में एक मजबूत ताकत

बनकर उभरी थी। इससे पहले स्वर्गीय तसलीमुद्दीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे। उनकी मौत के बाद सीमांचल की मुस्लिम आबादी नेतृत्व से वंचित हो गई थी। ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधान सभा के पिछले चुनाव में सीमांचल में पांच सीटों पर विजय प्राप्त की थी, मगर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मजलिस की कमर तोड़ हार के बाद बिहार में भी ओवैसी के नेतृत्व को गहरा झटका लगा है।

मजलिस में बगावत पर टिप्पणी करते हुए ए.आई.एम.आई.एम. के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट आदिल हुसैन ने कहा है कि उन्होंने सीमांचल की मुस्लिम जनता के साथ न केवल धोखा किया है बल्कि वे तेजस्वी यादव की कठपुतली बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी को लोकप्रिय बनाने में स्वर्गीय शहाबुद्दीन का महत्त्वपूर्ण योगदान था। उनके मरने के बाद उनके परिवार को पूरी तरह से भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी मुसलमानों की हमदर्द होती तो जब उसका नीतीश के साथ गठबंधन था उस समय वह उपमुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बनाती। बिहार में मुस्लिम जनता को ओवैसी के रूप में जो नेता मिला था उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है।

महाराष्ट्र में नगरों के नामों में परिवर्तन

औरंगाबाद टाइम्स (30 जून) ने आरोप लगाया है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद ऐतिहासिक नगर हैं। जिनकी संस्कृति और सभ्यता पर मुस्लिम छाप स्पष्ट है। मगर अपने राजनीतिक हितों के कारण महा विकास अघाडो सरकार के मुख्यमंत्री ने गद्दी छोड़ने से पूर्व दोनों नगरों के नाम बदल दिए। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। जब यह फैसला किया जा रहा था तो इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के दो मंत्री वर्षा गायकवाड और असलम शेख विरोध प्रकट करते हुए मीटिंग से बायकॉट कर गए। उद्धव ठाकरे के इस फैसले की महाराष्ट्र के विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने तीव्र आलोचना की है। इससे पूर्व भी 1995 में महाराष्ट्र की शिवसेना–भाजपा सरकार ने इनका नाम बदल दिया था। गत 27 वर्ष में नाम बदलने का यह दूसरा प्रयास है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पहले की तरह राज्य सरकार का यह फैसला अदालत में नहीं टिक पाएगा। 1995 में जब इन दोनों शहरों का नाम बदला गया था तो उसे कांग्रेस के एक कारपोरेटर मुस्ताक अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और वहां से स्टे मिल गया था। शिवसेना और भाजपा जब सत्ता विहीन हुई तो विलासराव देशमुख की सरकार ने पुरानी सरकार

के इस फैसले को रद्द कर दिया। मुस्ताक अहमद ने यह कहा है कि वे पुनः अदालत में जाएंगे।

औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबु आसिम आजमी ने खेद व्यक्त किया है और कहा है कि जिस सरकार का हम समर्थन कर रहे थे उसी ने उन नगरों के नाम बदल दिए, जिनसे मुस्लिम झलक नजर आती थी। अदालत ने जब मराठों के लिए आरक्षण को रद्द किया तो इसके साथ ही मुस्लिम आरक्षण भी रद्द कर दिया गया। उद्धव ठाकरे की सरकार में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को हाशिए पर रखा गया। जमीयत उलेमा के सचिव नदीम सिद्दीकी ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि वे इस संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

राष्ट्रपति का चुनाव उर्दू समाचारपत्रों की नजर में

दैनिक सियासत (28 जून) ने अपने संपादकीय में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के बीच उत्पन्न मतभेदों का उल्लेख किया है और कहा है कि प्रारंभ में ही विपक्षी दलों को अपना उम्मीदवार तय करने में भारी परेशानी हुई। सबसे पहले शरद पवार से इस संबंध में चर्चा हुई, मगर जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से संपर्क साधा गया। वे भी राजी नहीं हुए तो तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को इस उम्मीदवारी के लिए तैयार किया गया। हालांकि यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं, मगर उनकी पराजय निश्चित नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास मतों की भारी कमी है। हां, एक बात का उल्लेख करना जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां इस मामले में एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही हैं। एनडीए के उम्मीदवार की विजय इसलिए निश्चित है कि उसे आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है और बीजू जनता दल और बहुजन समाज पार्टी ने भी उसका समर्थन किया है। इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की विजय निश्चित नजर आ रही है।

राहुल गांधी का कहना है कि यह मुकाबला दो विचारधाराओं के बीच है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी इस विचार से सहमति प्रकट की है। लोकसभा के आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों को अभी से ही सत्तारूढ़ दल और भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए।

सालार ने 12 जून के संपादकीय में कहा है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति के संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के चयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शासनकाल में इतिहास पर कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ी है। भाजपा को कोई ऐसा उम्मीदवार चुनना होगा जो कि कई विपक्षी दलों के वोट भी पाने में समर्थ हो। अभी तक यह परंपरा रही है कि यदि

राष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल का होता है तो उपराष्ट्रपति विपक्षी दलों से चुना जाता है, मगर भाजपा के शासनकाल में इस परंपरा का पालन नहीं किया गया है। समाचारपत्र ने भाजपा को यह भी सलाह दिया है कि वह अपना उम्मीदवार किसी मुसलमान को बनाए ताकि अरब देशों में उसकी छवि सुधर सके।

सालार ने 20 जून के संपादकीय में कहा है कि विपक्षी दल किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को राष्ट्रपति के चुनाव में उतारने में विफल रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी दलों के बीच जिस तरह से मतभेद उत्पन्न हुए हैं उससे इस बात का संकेत मिलता है कि 2024 के लोक सभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाए जाने की संभावना नहीं है।

सालार ने 25 जून के संपादकीय में एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चयन का स्वागत किया है और कहा है कि उनकी विजय लगभग निश्चित है। अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए विजय प्राप्त करती हैं तो वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी।

इत्तेमाद ने 14 जून के संपादकीय में अगले राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा का पलड़ा भारी है। सत्तारूढ़ दल के पास 10 लाख 79 हजार वोटों में से 49 प्रतिशत वोट हैं। उसके पास सिर्फ 13 हजार वोटों की कमी है। कांग्रेस और उसके सहायक पार्टियों के पास 22 प्रतिशत और गैरकांग्रेसी गठबंधन के पास 29 प्रतिशत वोट हैं। जिस तरह से कुछ विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है उससे यह साफ है कि उन्हें विजय प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी।

सालार (23 जून) ने कहा है कि एनडीए ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पुनः चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। बल्कि उनके स्थान पर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्म् को मैदान में उतारा है जो उड़ीसा की रहने वाली हैं और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वह दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। 17 विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस के यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों उम्मीदवार पूर्वी भारत के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में देश की जनता सीधा भाग नहीं लेती है, बल्कि राष्ट्रपति का चयन संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों के विधान सभाओं और विधान परिषद के सदस्य मिलकर करते हैं। अभी तक विपक्षी दलों का कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हो पाया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 जून) ने अपने संपादकीय में इस बात पर खेद प्रकट किया है कि देश के विपक्षी दल संयुक्त उम्मीदवार का चयन करने में विफल रहे हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि हालांकि संसद में भाजपा का भारी बहुमत है, मगर विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों का पलड़ा भारी है। जिस तरह से ममता बनर्जी द्वारा आयोजित बैठक में 22 विपक्षी दलों में से केवल 16 ही शामिल हुए उससे यह साफ है कि भाजपा क उम्मीदवार का विजय प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा कर चुके हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जून) ने आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ दल राष्ट्रपति के चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को अपदस्थ किया गया है। नीतीश कुमार भी दिल्ली के निशाने पर आ सकते थे, मगर उन्होंने मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा करके फिलहाल शांति खरीद ली है। ममता बनर्जी न आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के चुनाव मं जीत के लिए भाजपा विपक्षी दलों को तोड़ने का प्रयास कर रही है और इसीलिए उनके पीछे सीबीआई और ईडी को लगा दिया गया है।

अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही

हमारा समाज (23 जून) के अनुसार अफगानिस्तान में भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है और कम-से-कम 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं तथा 2000 घायल हो गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रिक्टर स्केल थी। पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। चारों तरफ मलवे और लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हालांकि राहत और सहायता कार्य शुरू कर दिया है, किंतु दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों से जख्मियों को लाना संभव नहीं है। तालिबान सरकार ने कहा है कि इस भूकंप के कारण हजारों मकान गिर गए हैं, इसलिए मृतकों की संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना है। तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता की अपील की है और साथ ही अमेरिका से यह अनुरोध किया है कि उसने अफगान सरकार की जिस धनराशि को फ्रिज कर रखा है उसे मानवीय आधार पर तुरंत रिलीज किया जाए, ताकि सहायता कार्य को तेज करने में मदद मिल सके। पाकिस्तान सरकार ने इस भूकंप में आई तबाही पर दु:ख व्यक्त किया है और यह घोषणा की है कि पाकिस्तान सरकार अफगान जनता को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। भारत के विदेश मंत्री ने भी अफगान सरकार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 2002 में भी इस क्षेत्र में भूकंप आया था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

रोजनामा सहारा (28 जून) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि मानवीय आधार पर अमेरिका अफगानिस्तान सरकार को सहायता देने पर विचार कर रहा है।

इंकलाब (27 जून) के अनुसार तालिबान ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह तालिबान सरकार पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का वापस ले और अफगान सेंट्रल बैंक की प्रतिभूतियों पर लगाए गए प्रतिबंध को फौरन हटाए। अफगान सरकार के विदेश मंत्रालय ने विश्व के सभी देशों को इस मुश्किल घड़ी में सहायता उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

रोजनामा सहारा (1 जुलाइ) के अनुसार अमेरिका सरकार द्वारा फ्रीज की गई अफगान सेंट्रल बैंक की धनराशि की वापसी के बारे में

अमेरिका और तालिबान के बीच दुबई में वार्ता शुरू हो गई है। इस वार्ता में अफगान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और अमेरिका के विशेष दूत थॉमस वेस्ट हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी सरकार के एक प्रतिनिधि ने यह कहा है कि यह वार्ता संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर शुरू की जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग अकाल और भूख का शिकार हैं। अमेरिका सरकार के एक प्रतिनिधि न कहा कि पिछले वर्ष अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अफगान सेंट्रल बैंक की नौ बिलियन डॉलर की धनराशि को फ्रीज कर दिया था। इसके अतिरिक्त अनेक देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता को बंद कर दी थी। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल अमेरिका सात बिलियन डॉलर में से आधी धनराशि को अफगान सरकार को रिलीज करने पर विचार कर रहा है।

पाकिस्तान को आर्थिक दिवालियापन से बचाने का प्रयास

हमारा समाज (9 जून) के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट का शिकार है और उसे इस संकट से उबरने के लिए अगले 12 महीने में 41 अरब डॉलर की आवश्यकता है। अगर इस धनराशि की व्यवस्था नहीं हुई तो पाकिस्तान को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। बजट से पूर्व एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष हमें विदेशी कर्ज की 21 अरब डॉलर की धनराशि को वापस करना होगा और यह तभी संभव है जब हमें विदेशों से 41 अरब डॉलर की सहायता प्राप्त हो। मैं आशा करता हूं कि हमें विदेशी स्रोत सहायता करेंगे और शीघ्र ही आईएमएफ के साथ हमारा समझौता भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने देश को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने पर विवश हैं। हमें इस समय डीजल पर 4.5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 7 रुपये प्रति लीटर नुकसान हो रहा है। अगर हम सब्सिडी देने का सिलसिला जारी रखते हैं तो यह नुकसान 20 अरब रुपये महीना होता है। जबकि सरकार का प्रशासन चलाने का खर्च 40 अरब रुपये है।

उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने आईएमएफ से यह वायदा किया था कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसलिए पुरानी सरकार ने 30 रुपये प्रति लीटर टैक्स को बढ़ा दिया था और 17 प्रतिशत सेल टैक्स भी लगा दिया था। अगर इमरान सरकार के शासनकाल में किए गए इस समझौते को कार्यान्वित किया जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाएगी। इमरान सरकार ने नई सरकार को दलदल में फंसाने के लिए ये समझौते किए थे। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम इस समझौते के दलदल से कैसे निकलें। यही कारण है कि हम सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और इन देशों का रवैया सकारात्मक भी है। उन्होंने कहा कि 71

वर्ष की अवधि में पाकिस्तान के शासकों ने 25 हजार अरब रुपये के कर्ज लिए थे। जबकि इमरान सरकार ने सिर्फ चार वर्ष की अवधि में 20 हजार अरब के कर्ज लिए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकट में फंस गया है।

रोजनामा सहारा (29 जून) के अनुसार पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां के हिस्सों को खरीदने की पेशकश की है। पाकिस्तान सरकार ने यह भी कहा है कि वह इन सरकारी कंपनियों में संयुक्त अरब अमीरात का एक एक निदेशक नियुक्त करने के लिए तैयार है। एक अन्य सूचना के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को दो अरब डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सरकारी सूत्रों से कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों के 10-12 प्रतिशत हिस्सों को खरीदने का प्रस्ताव किया है। पाकिस्तान सरकार यह प्रयास कर रही है कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ होने वाले समझौते में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे एक अवधि के बाद पाकिस्तान सरकार इन हिस्सों को वापस खरीद सके। संयुक्त अरब अमीरात ये हिस्से वेल्थ फंड डेवलपमेंट होल्डिंग के माध्यम से खरीद रही है।

हाल ही में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त अरब अमीरात गए थे तो उन्होंने वहां की सरकार से अनुरोध किया था कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए संयुक्त अरब अमीरात आगे आए। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आया था और उसने पाकिस्तान सरकार को तुरंत दो अरब डॉलर सहायता देने का प्रस्ताव किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने यह स्वीकार किया है कि 2019 में तयशुदा

समझौते के अनुसार पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को दो अरब डॉलर का कर्ज वापस नहीं किया था, इसलिए वहां से नया कर्ज प्राप्त करने में पाकिस्तान सरकार को परेशानी हो रही है।

सियासत (20 जून) ने अपने संपादकीय में यह आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह धमकी दी थी कि वह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर देगा। उसने हाल ही में पाकिस्तान दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान सरकार इस समझौते की शर्त को पूरा कर रही है कि वह आतंकवादी संगठनों को किसी तरह की सहायता नहीं करेगा।

समाचारपत्र के अनुसार चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 में पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में किसी भी आतंकवादी संगठन को किसी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगी। इसलिए इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान को इस आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी।

काबुल में गुरुद्वारे में धमाका

अवधनामा (19 जून) के अनुसार काबुल में एक गुरुद्वारे पर इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने हमला करके कई सिख श्रद्धालुओं की हत्या कर दी और दर्जनों को घायल कर दिया। बताया जाता है कि जब आतंकियों ने गुरुद्वारे पर हमला किया तो गुरुद्वारे की रक्षा के लिए नियुक्त तालिबानी रक्षकों से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन तालिबानी रक्षक मारे गए। इसके अतिरिक्त कम-से-कम दो सिख श्रद्धालुओं के भी मारे जाने की खबर है। धमाके में मारे जाने वाला एक सिख व्यक्ति का नाम सविन्द्र सिंह है, जिसका परिवार दिल्ली में रहता है। भारत सरकार ने गुरुद्वारे पर हमले पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंढोक ने कहा है कि आतंकवादियों ने पहले गुरुद्वारे पर बमों से हमला किया था। इसके बाद सशस्त्र आतंकवादी गुरुद्वारे में दाखिल हो गए और उन्होंने वहां पर कीर्तन कर रहे दो दर्जन श्रद्धालुओं को अपना बंधक बना लिया। बाद में तालिबान ने सैनिक भेजकर इन बंधकों को मुक्त करवाया। इस मुठभेड़ में अनेक आतंकवादी एवं अफगान सेना के लोग मारे गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (20 जून) के अनुसार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने गुरुद्वारे पर हमले की जिम्मेवारी ली है और कहा है कि उसने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि भारत में पैगम्बर की तौहीन करने वाले भाजपा के दो प्रवक्ताओं के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमलावरों ने गुरुद्वारे में पहले एक बम फेंका था, जिससे वहां पर आग लग गई। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस अफगानिस्तान में मासूम लोगों की जान स खेल रहा है।

अमेरिका में गन कल्चर को रोकने के प्रयासों को झटका

अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर मासूम लोगों की जान लेने की जो प्रवृत्ति गत कुछ वर्षों से बढ़ रही थी, उसको अमेरिकी सरकार सख्ती से रोकना चाहती थी, मगर हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण इन प्रयासों को जबर्दस्त झटका लगा है।

रोजनामा सहारा (25 जून) के अनुसार अमेरिका की सवोर्च्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अमेरिकियों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी रक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हथियार अपने साथ लेकर जा सकते हैं। यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी सरकार अंधाधुंध फायरिंग करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए अमेरिकी संसद द्वारा एक महत्त्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के सभी छह कंजर्वेटिव न्यायाधीशों ने इस फैसले के पक्ष में वोट दिए जबकि तीन लिबरल न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया। संवाद समिति 'एसोसिएटेड प्रेस' के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने 1913 से न्यूयार्क में लागू एक कानून को समाप्त कर दिया था, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र ले जाने के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु ठोस वजह बताना जरूरी था। इस फैसले को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी थी। हाल के फैसले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी पाबंदी अमेरिकी संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों को अस्त्र-शस्त्र रखने की खुली छूट है। इस तरह के कानून न्यूयॉर्क के अतिरिक्त अमेरिका के छह अन्य राज्यों में भी लागू हैं। इनमें कैलिफोर्निया, हवाई, मेरीलैंड, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड शामिल हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में कुल नौ न्यायाधीश हैं। इनमें मुख्य न्यायाधीश और शेष सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों के लिए कोई कार्यावधि नहीं है। वे जब चाहें अपने पद से अवकाश ले सकते हैं। उनके स्थान पर राष्ट्रपति नए न्यायाधीश को मनोनीत करता है और उसकी अनुमति बाद में सीनेट से प्राप्त की जाती है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति जो

बाइडेन ने निराशा व्यक्त की है और कहा है कि इससे देश में बढ़ते हुए गन कल्चर की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे इस फैसले के खिलाफ एकजुट हों और गन सेफ्टी के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि उनका जीवन दांव पर लगा हुआ है। इस फैसले से अमेरिका की एक चौथाई आबादी प्रभावित होगी।

इससे पूर्व **इंकलाब** (25 जून) के अनुसार अमेरिकी सीनेट ने गन नियंत्रण विधेयक को मंजूरी दे दी थी जो कि हथियारों के इस्तमाल की रोकथाम के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कानून है। अमेरिकी सीनेट के 66 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मत दिए थे जबकि 33 ने इसका विरोध किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के 51 और रिपब्लिकन पार्टी के 15 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिए। यह विधेयक उस समय मंजूर हुआ जब मई में न्यूयॉक और टेक्सास में कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोली चलाकर 31 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस बात की संभावना थी कि यह नया विधेयक कांग्रेस में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रपति मंजूरी दे देंगे और यह कानून बन जाएगा। सीनेट में इस बिल की मंजूरी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन न कांग्रेस से अनुरोध किया था कि इस विधेयक को शीघ्र अति शीघ्र पास किया जाए, ताकि अमेरिका में मासूम लोगों की हत्याओं को रोका जा सके। इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि अस्त्र-शस्त्र खरीदने वाले 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को लाइसेंस देने से पूर्व उनके बारे में कड़ी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में यह आशंका हो कि वह अपने हथियार का गलत इस्तेमाल करेगा तो उससे वह हथियार वापस लिया जा सकता है। इस कानून के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को भी हथियार खरीदने की अनुमति नहीं होगी जो घरेलू हिंसा के आरोप में सजा काट चुका हो।

बलूचिस्तान में मजदूरों के शिविर पर विद्रोहियों का हमला

रोजनामा सहारा (19 जून) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला हरनाई में मजदूरों के एक कैंप पर प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड बलूच आर्मी ने हमला करके तीन लोगों की हत्या कर दी और और सात लोग लापता हो गए। यूनाइटेड बलूच आर्मी ने यह हमला एक निजी कंपनी द्वारा सड़क बनाने को रोकने के लिए किया। यूनाइटेड बलूच आर्मी का आराप है कि पाकिस्तान सरकार इस तरह की सड़कों का निर्माण इसलिए कर रही है, ताकि पंजाबी पूंजीपति बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का दोहन कर सकें। बलूचिस्तान के कुछ संगठन काफी समय से पाकिस्तान सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को वहां के स्थानीय लोगों के लिए वंचित करना चाहती है और उन्हें पंजाबी उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है, ताकि बलूचिस्तान का विकास न हो और वह पिछड़ा बना रहे।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुदुस बिजंजो ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों के उकसाने पर य कठपुतली संगठन बलूचिस्तान में अशांति पैदा कर रहे हैं और विकास कार्यक्रमों को रोक रहे हैं। इससे पूर्व भी बल्चिस्तान में सड़कों का निर्माण करने वाले मजदूरों पर कई घातक हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों के बाद कई सड़कों का निर्माण कार्य ठप हो गया है। गत वर्ष बलूच लिब्रेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में बांध का निर्माण करने वाले एक दर्जन चीनी इंजीनियरों को मौत के घाट उतार दिया था।

इजरायली संसद भंग और नया चुनाव

रोजनामा सहारा (25 जून) के अनुसार इजरायली सांसदों ने एक विधेयक पारित करके संसद को भंग करने और नए चुनाव करवाने की मंजूरी दे दी है। इजरायल के इतिहास में पहली बार इजरायली संसद के चुनाव 4 वर्ष से भी कम की अवधि में पांचवीं बार हो रहे हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट के गठबंधन के सदस्यों के त्यागपत्र के बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में बने विपक्षी दलों द्वारा संसद को भंग करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि नाफ्ताली बेनेट के संयुक्त गठबंधन को संसद में बहुमत नहीं रहा था। सत्तारूढ़ मोर्चा का इस बात के लिए आग्रह था कि इजरायल में पुनः चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि एक वर्ष पूर्व जो गठजोड़ बना था उसमें मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। नेसेट हाउस कमेटी ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसे जब सदन में पेश किया गया तो इसका समर्थन 53 सदस्यों ने किया और इसका विरोध किसी ने नहीं किया। संसद के भंग हो जाने के बाद नए चुनाव अक्टूबर या नवंबर के पहले सप्ताह में किए जाने की संभावना है।

रोजनामा सहारा (28 जून) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने यह घोषणा की है कि वे आने वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मंत्रिमंडल के भंग होने के बाद उनके एक प्रवक्ता ने घोषणा की कि आठ दलों के संयुक्त गठबंधन की ओर से यैर लापिद नए कार्यकारी प्रधानमंत्री होंगे। गौरतलब है कि एक वर्ष पूर्व नाफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू के 12 वर्षीय शासन का अंत कर दिया था। मनोनीत नए प्रधानमंत्री पूर्व पत्रकार हैं और गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल के प्रमुख हैं। अगले चुनाव होने तक वे कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज का कहना है कि हमारी सरकार ने गत एक वर्ष में शानदार कार्य किया था। यह शर्म की बात है कि देश को पुनः एक चुनाव का सामना करना पड़ा है।

इजरायल में संसदीय संकट ऐसे समय में उत्पन्न हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन

इजरायल का दौरा करने की घोषणा कर चुके हैं। उनके इस दोरे का मुख्य लक्ष्य ईरान के खिलाफ अरब देशों का मोर्चा बनाना है। हालांकि नाफ्ताली की नई सरकार ने नेतन्याहू सरकार के शासन का खात्मा कर दिया था, मगर आठ पार्टियों का जो नया गठबंधन बना था उसमें वाम दल, लिबरल और अरब मुस्लिम दल शामिल थे। इनके बीच जबर्दस्त सैद्धांतिक मतभेद थे। यही कारण है कि सत्तारूढ़ मोर्चे के चार सांसदों के त्यागपत्र के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन का संसद में बहुमत समाप्त हो गया। इस बात की संभावना है कि नेतन्याहू ही शायद पुनः प्रधानमंत्री का पद संभाल लें।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 जून) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजरायल के संसदीय संकट के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जुलाई के महीने में इजरायल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल हमारा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक साझीदार है। इसके साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में हमारा सहयोग जारी रहेगा। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल के साथ हमारे जिस तरह के संबंध हैं उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट हाउस में कौन राष्ट्रपति है या इजरायल का कोन प्रधानमंत्री है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार नेतन्याहू के पुनः सत्ता में आने की संभावना है। उन्हें दक्षिणपंथी माना जाता है। ओबामा सरकार के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। दक्षिणपंथी कट्टर यहूदी होने के कारण नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अरब जगत में किए जा रहे प्रयासों से स्वयं को अलग कर लिया था। इसके बावजूद अब बदले हुए हालात के कारण इजरायल को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा है।

ईरान और सऊदी अरब के संबंध सुधारने हेतु इराक प्रयासरत

इंकलाब (28 जून) के अनुसार ईरान क सरकारी टीवी के अनुसार इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी ने सऊदी अरब का दौरा करने और वहां के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करने के बाद फौरन तेहरान जाकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। बाद में इन दोनों ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में बताया कि हमने इस क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यमन में जो गृहयुद्ध चल रहा है उसका जल्द-से-जल्द खात्मा हो ताकि अरब जगत में शांति स्थापित हो सके। इससे पूर्व इराक के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। हम यमन में गृहयुद्ध से चिंतित हैं। हमारा यह विश्वास है कि इस युद्ध के कारण अरब जगत में तनाव आया है और यमन की जनता तबाह हो गई है। वहां पर भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए यह जरूरी है कि इस गृहयुद्ध को रोका जाए ताकि स्थिति सामान्य हो सके। इराक के प्रधानमंत्री न ईरान का दौरा करने से पूर्व सऊदी अरब का दौरा किया था। सऊदी अरब की सरकारी संवाद समिति 'एस.पी.ए.' के अनुसार इस बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और अरब जगत में शांति स्थापित करने का समर्थन किया गया। कादिमी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिमी देश यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण अरब के तेल उत्पादक देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख ने भी हाल में ईरान का दौरा किया था और उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में वार्ता पुनः शुरू की

जाएगी ताकि जो गतिरोध पैदा हुआ है उसे दूर किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति भी अगले महीन सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं।

इस संदर्भ में यह बात उल्लेखनीय है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच गत एक दशक से काफो तनाव चल रहा है। 2016 में जब सऊदी अरब ने विख्यात शिया विद्वान निमर अल-निमर को फांसी दी थी तो उसके खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन हुए थे, जिसमें तेहरान स्थित सऊदी दूतावास को आग लगा दी गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हो गए थे। कहा जाता है कि यमन मं हूती विद्रोहियों द्वारा जो सऊदी अरब के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। सऊदी अरब यमन की पुरानी सरकार का समर्थन करता है जबकि ईरान का समर्थन हूती विद्रोहियों को है। इराक ने पिछले वर्ष भी सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया था, मगर सऊदी अरब द्वारा 40 शिया नेताओं को फांसी पर लटकाने के कारण उसके ये प्रयास विफल हो गए थे और दोनों देशों के बीच पुनः तनाव पैदा हो गया था।

इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में जनरल गिरफ्तार

अमेरिकी अखबार **न्यूयॉर्क टाइम्स** के अनुसार ईरानी सरकार ने गुप्तचर संगठन पासदारान-ए-इंकलाब के एक महत्त्वपूर्ण जनरल को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर ईरान में सत्तारूढ़ उच्चस्तरीय सूत्रों के हवाले से दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि मेजर जनरल अली नासिरी को सेना ने गुप्त रूप से गिरफ्तार किया है। वे पासदारान-ए-इंकलाब की सूचना सुरक्षा इकाई के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे, जिसे ईरानी गुप्तचर तंत्र का सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली अंग माना जाता है। बताया जाता है कि इससे पूर्व ईरान के गुप्तचर विभाग ने रक्षा मंत्रालय के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के दर्जनों कर्मचारियों को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद मेजर जनरल नासिरी को गिरफ्तार किया गया

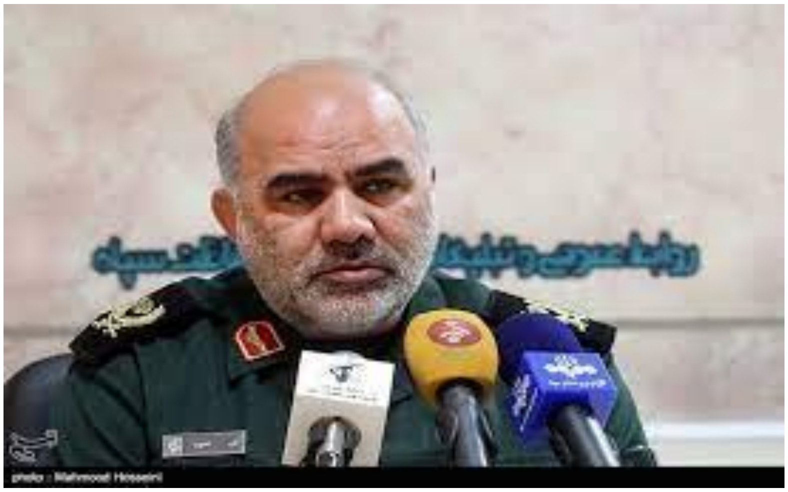

उनके पद से इसलिए हटा दिया गया था, क्योंकि ईरानी गुप्तचर विभाग इजरायली गुप्तचर तंत्र का सुराग लगाने में विफल रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए बढ़ते हुए इजरायली खतरे का सामना करने के लिए यह जरूरी है कि ईरानी गुप्तचर एजेंसियों का पुनर्गठन किया जाए, ताकि ईरान की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में

है। कहा जाता है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल डिजाइन के ब्लूप्रिंट इजरायल को लीक किए थे।

अमेरिकी समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अली अबताही ने यह स्वीकार किया था कि ईरान की गुप्तचर विभाग के प्रमुख हुसैन ताएब को अचानक

इजरायल के घुसपैठ को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि परेशानी यह है कि हमारी गुप्तचर व्यवस्था कई दशक पुरानी है। हमारे तंत्र में अनेक ऐसे दोष हैं, जिनके कारण हम अपने देश में विदेशी गुप्तचरों की गतिविधियों का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं।

तुर्की और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास

रोजनामा सहारा (23 जून) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में तुर्की का दौरा किया था। उनकी वहां के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ काफी लंबी बातचीत हुई थी। इस दौरे का लक्ष्य सऊदी पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या के कारण दोनों देशों के बीच आए तनाव को दूर करना है। मीडिया के अनुसार दोनों देश पिछले कुछ महीनों से अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी सिलसिले में एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था। इस दौरे का लक्ष्य इस्तांबुल में जमाल खशोग्गी के कत्ल के मुकदमे को समाप्त करना भी था। उन्होंने इस संदर्भ में सऊदी अरब के युवराज से भी लंबी बातचीत की थी। सऊदी युवराज ने तुर्की के राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया था कि आर्थिक संकट के मझधार से तुर्की को उबारने के लिए सऊदी अरब तुर्की में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करेगा।

तुर्की के वरिष्ठ अधिकारी ने 'रॉयटर्स' को बताया कि हमें इस बात की आशा है कि इन दोनों महत्त्वपूर्ण इस्लामिक देशों के संबंध शीघ्र ही सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की में तेजी से कम हो रहे विदेशी मुद्रा के भंडारों की समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि हमें सऊदी अरब सहयोग दे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के कारण तुर्की की आर्थिक बदहाली में वृद्धि हुई है। तुर्की की मुद्रा का मूल्य विदेशी बाजार में गिरा है और देश में मूल्य वृद्धि तेजी से हुई है। इस बात की संभावना है कि दोनों देशों के बीच औद्योगिक

साझेदारी बढ़ाने और पूंजी निवेश में वृद्धि करने के बारे में महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछल तीन वर्ष में पहली बार मोहम्मद बिन सलमान ने किसी मुस्लिम देश का दौरा किया है। इससे पूर्व वे जॉर्डन भी गए थे। उनका तुर्की का यह दौरा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि शीघ्र ही तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए एर्दोगान को देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होगा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को समाप्त करना होगा। यह सऊदी अरब के सहयोग के बिना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि 2018 में सऊदी अरब के एजेंटों ने तुर्की के इस्तांबुल में एक सऊदी पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। यह पत्रकार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान का आलोचक था। तुर्की के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि इस पत्रकार की हत्या के पीछे सऊदी अरब के शाही खानदान का हाथ है। बाद में अरब देशों के दबाव पर तुर्की ने इस मुकदम की सुनवाई रोककर इसे सऊदी अरब में स्थानांतरण कर दिया था, जिसकी विश्व भर में तीखी आलोचना हुई थी। मानवाधिकार संगठनों ने कहा था कि तुर्की ने खैरात पाने के लिए अपनी इज्जत का सऊदी अरब से सौदा किया है। गत कुछ दिनों में तुर्की की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है और महंगाई में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, उसके कारण तुर्की को सऊदी अरब के साथ संबंधों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पड़े हैं।

सऊदी अरब और तुर्की के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए **इत्तेमाद** (24 जून) ने कहा है कि आलम-ए-इस्लाम के दो महत्त्वपूर्ण देशों सऊदी अरब और तुर्की के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास पूरे मुस्लिम जगत के लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मध्य-पूर्व में युद्ध और कोरोना के कारण आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। यह जरूरी है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए इस्लामिक देश एक दूसरे को सहयोग दें। मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की का दौरा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। तुर्की में सऊदी अरब के पत्रकार की हत्या के कारण जो तनाव

उत्पन्न हुआ था, उसके बाद सऊदी अरब ने तुर्की से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण पांच अरब डॉलर की क्षति हुई थी। अब तुर्की में बढ़ते हुए आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रपति एर्दोगान को सऊदी अरब का हाथ थामना पड़ा है। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इजरायल के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है, ताकि वह समस्याओं के मकड़जाल से मुक्ति पा सके। सऊदी अरब और तुर्की के संबंधों में तनाव की शुरुआत एक दशक पूर्व हुई थी, जब मिस्र में अब्दुल फतह अल-सिसी ने 2013 में इख्वानुल मुस्लिमीन की सरकार का खात्मा कर दिया था और राष्ट्रपति का पद स्वयं संभाल लिया था। तुर्की ने अल-सिसी को मान्यता देने से इंकार कर दिया था। सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश जहां पर सुल्तानों और बादशाहों की हुकूमत है, इख्वानुल मुस्लिमीन के ताकतवर होने से उनकी बादशाहत और गद्दी खतरे में पड़ने की संभावना लग रही थी।

तुर्की और सऊदी अरब के बीच तनाव में उस वक्त भी और वृद्धि हुई जब सऊदी अरब ने कतर की जो नाकाबंदी की थी उसे विफल बनाने के लिए तुर्की ने प्रयास किया था। दोनों देशों के बीच 2017 से 2021 तक राजनयिक संबंध नहीं रहे। बाद में तुर्की के प्रयासों से इन संबंधों को बहाल किया गया था। सऊदी पत्रकार की हत्या के बाद तुर्की को व्यापारिक क्षति उठानी पड़ी थी। इसलिए अब तुर्की का यह प्रयास है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सऊदी सरकार के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जाए। सऊदी सरकार का भी यह प्रयास है कि वह ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए तुर्की के साथ अपने संबंधों को सुधारे। यही कारण है कि सऊदी युवराज ने हाल ही में तुर्की का दौरा किया है।

ईरान में तीन महीने में सौ से अधिक लोगों को फांसी

इंकलाब (23 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ईरान में फांसी दिए जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के प्रारंभिक तीन महीनों में ईरान में सौ से अधिक लोगों को फांसी पर लटकाया गया है, जबकि 2020 में ईरान में 260 लोगों को फांसी दी गई थी वहीं 2021 में 310 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल थीं। जिन लोगों को फांसी दी गई उनमें से अधिकांश सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थे।

गौरतलब है कि ईरान में शियाओं का शासन है। ईरान सऊदी अरब पर प्रायः यह आरोप लगाता रहा है कि वह अपने देश में असंतुष्ट शिया नेताओं को झूठे आरोपों में फांसी पर लटकाता है और इसका कारण धार्मिक द्वेष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान में मौत की सजा के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा है कि अक्सर लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य छोटे-मोटे अपराधों में लिप्त होने के कारण फांसी पर लटकाया गया। अधिकांश मामलों में आरोपियों को अपना पक्ष अदालत में पेश करने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अवसर ही दिया गया। वहां पर अनेक किशोरों को भी फांसी पर लटकाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।

ब्रिटेन में हजरत फातिमा पर बनी फिल्म पर पाबंदी

सियासत (10 जून) के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के दबाव पर हजरत फातिमा पर बनी एक फिल्म 'द लेडी ऑफ हैवेन' के प्रसारण पर रोक लगा दी है। मुसलमानों के संगठन मुस्लिम काउंसिल ने इस फिल्म को अपमानजनक करार दिया था और उन सिनेमाघरों पर विरोध प्रदर्शन भी किए थे, जिनमें इस फिल्म को दिखाया जा रहा था। यह फिल्म सिनेवर्ल्ड नामक कंपनी ने बनाई थी। इस कंपनी ने कहा है कि सुरक्षा के दृष्टि से उसके कर्मचारियों का जीवन खतरे में पड़ गया था, इसलिए इसके प्रसारण को रोकने का फैसला किया गया है। कंपनी ने कहा है कि यह फिल्म पैगम्बर की बेटी हजरत फातिमा के जीवन पर आधारित है और उसमें उन पर किसी तरह की छींटाकशी नहीं की गई। इस फिल्म में हजरत फातिमा की भूमिका निभाने वाली महिला को एक काला नकाब पहने हुए दिखाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में उर्दू और हिंदी

सियासत (12 जून) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में उर्दू और हिंदी को भी अधिकृत रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इनके अतिरिक्त पुर्तगाली, फारसी और बांग्ला का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की छह अधिकृत सरकारी भाषाएं हैं, जिनमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को पहली बार हिंदी भाषा में संबोधित किया था।

बेंगलुरु में ईदगाह की भूमि पर विवाद

सियासत (18 जून) के अनुसार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईदगाह की भूमि के इस्तेमाल पर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों श्रीराम सेना, हिंदू संगठन परिषद और कुछ अन्य संगठनों ने ईदगाह मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बेंगलुरु महानगर निगम से अनुमति मांगी थी। वे चामराजपेट स्थित ईदगाह मैदान में योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव मनाना चाहते थे। उनका दावा था कि यह मैदान महानगर निगम का है। जबकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इस भूमि पर अपना दावा पेश किया है। उनका कहना है कि यह वक्फ संपत्ति है और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1964 में एक फैसले में इसे ईदगाह की भूमि घोषित कर चुका है और इस संबंध में 7 जून 1965 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। इसलिए इस भूमि पर किसी अन्य धर्म से संबंधित समारोह का आयोजन नहीं किया जा सकता। महानगर निगम इस संदर्भ में कानूनी विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

सऊदी अरब सरकार द्वारा इस्लामिक आतंकियों को मृत्युदंड का स्वागत

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जून) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने लेबनान की एक विशेष अदालत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरिरी की हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा देने का स्वागत किया है। इन दोनों आरोपियों का संबंध हिजबुल्लाह नामक शिया आतंकवादी संगठन से बताया जाता है। गौरतलब है कि इस विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरिरी सहित 22 अन्य लोगों की हत्या करने का इन इस्लामिक आतंकियों को दोषी करार दिया है। इस हमले में कम-से-कम 226 लोग घायल भी हो गए थे। विशेष अदालत ने कहा है कि इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह नामक इस्लामिक जिहादी संगठन का हाथ है, जिसके तार ईरान से जुड़े हुए हैं।

ब्रिटिश टीवी चैनल बीबीसी पर जुर्माना

मुंबई उर्दू न्यूज (16 जून) के अनुसार ब्रिटिश चैनल बीबीसी ने लेबर पार्टी से संबंधित बांग्लादेशी मूल की कॉन्सिलर लीजा बेगम को 30 हजार पाउंड जुर्माना अदा करने का फैसला किया है। बीबीसी ने अपनी एक खबर में अप्साना बेगम के स्थान पर लीजा बेगम की तस्वीर दिखाई थी। 29 अक्टूबर 2020 को बीबीसी के प्रतिनिधि ने लीजा बेगम की तस्वीर को दिखाते हुए कहा था कि यह अप्साना बेगम है, जिस पर फ्रॉड के तीन मुकदमे चल रहे हैं। इस खबर के प्रसारण के बाद लीजा बेगम ने चैनल के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। इस पर अदालत ने 30 हजार पाउंड का जुर्माना चैनल पर लगाया है और उसे लीजा बेगम को अदा करने का निर्देश दिया है। लीजा बेगम पिछले वर्ष वेस्ट मिनिस्टर काउंसिल का चुनाव जीती थीं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

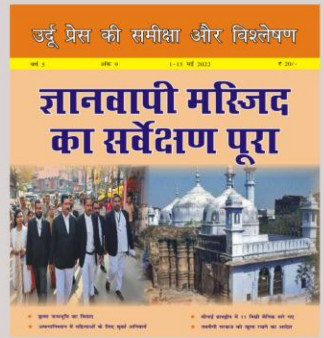

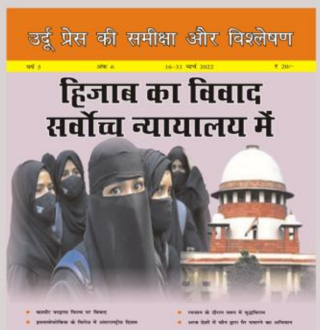

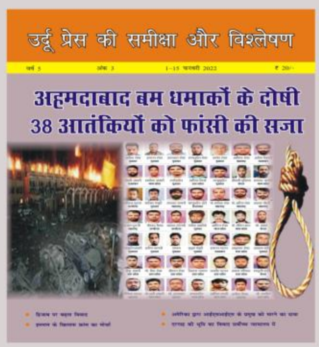

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in